

इज़राइल को अस्तित्व का अधिकार नहीं है

इज़राइल का एक राष्ट्र के रूप में स्थापना और 1949 में संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रवेश शांति, अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन, और न्याय व आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के प्रति सम्मान के वादों पर आधारित था। हालांकि, सात दशकों से अधिक समय तक, इज़राइल ने व्यवस्थित रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य किया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में इसकी वैधता कमजोर हुई है, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है, यहूदी नैतिक आदेशों की अवहेलना की गई है, और ऐसी कार्रवाइयों की गई हैं जो नरसंहार की कानूनी परिभाषा के अनुरूप हैं। यह निबंध तर्क देता है कि इज़राइल की निरंतर अवज्ञा, दंडमुक्ति, और एक यहूदी राष्ट्र के रूप में इसकी गलत प्रस्तुति न केवल इसकी नैतिक और कानूनी स्थिति को अमान्य करती है, बल्कि विश्व भर के यहूदियों को अत्याचारों से जोड़कर उन्हें खतरे में डालती है। इसके अतिरिक्त, यह पुष्टि करता है कि फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिरोध और आत्मनिर्णय का अविचल अधिकार है, जबकि यह तर्क देता है कि इज़राइल, एक राष्ट्र के रूप में, अस्तित्व का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं रखता, जो एक विशेषाधिकार है जो व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, न कि राजनीतिक संस्थाओं के लिए।

संयुक्त राष्ट्र में दुर्भावनापूर्ण प्रवेश

जब इज़राइल ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन किया, तो उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 4 के तहत ऐसा किया, जिसमें यह आवश्यक है कि सदस्य “शांतिप्रिय राष्ट्र” हों जो चार्टर के दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हों। बहस के दौरान, इज़राइल के प्रतिनिधि, अब्बा इबन, ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 181 (1947), जो फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राष्ट्रों में विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत करता था, और प्रस्ताव 194 (1948), जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी या मुआवजे को अनिवार्य करता था, का पालन करने की स्पष्ट गारंटी दी। इबन ने कहा: “इज़राइल प्रस्ताव 194 को लागू करने में संयुक्त राष्ट्र के अंगों और एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है” (संयुक्त राष्ट्र तदर्थ राजनीतिक समिति, 47वीं बैठक, पृ. 282)। ये आश्वासन 11 मई 1949 को प्रस्ताव 273(III) के माध्यम से प्रवेश के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण थे।

हालांकि, 1949 के बाद से इज़राइल की कार्रवाइयां एक सुनियोजित दुर्भावना को दर्शाती हैं। इसने न तो विभाजन योजना की सह-अस्तित्व की दृष्टि का सम्मान किया और न ही फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी को सुगम बनाया। इसके बजाय, इज़राइल ने क्षेत्रीय विस्तार, जातीय विस्थापन, और व्यवस्थित दमन की नीति अपनाई, जिससे इसके प्रारंभिक वचन खोखले हो गए। सामान्य कानून में, झूठे बहाने के तहत किया गया या दुर्भावनापूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया अनुबंध रद्द किया जा सकता है। इसी तरह, इज़राइल का संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के दायित्वों को पूरा करने में विफलता—विशेष रूप से प्रस्ताव 181 और 194 के प्रति इसकी अवहेलना—इसके सदस्यता को अमान्य करने के लिए तर्क दिया जा सकता है। जैसा कि वियना संधि कानून संधि (अनुच्छेद 26) निर्धारित करता है: “हर लागू संधि इसके पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है और इसे उनके द्वारा सद्भावना के साथ निष्पादित किया जाना चाहिए।” इज़राइल के निरंतर उल्लंघन इस सिद्धांत के उल्लंघन का संकेत देते हैं, जो इसके संयुक्त राष्ट्र की स्थिति की वैधता को कमजोर करता है।

संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और ICJ निर्णयों का अनुपालन न करना

इज़राइल का संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णयों के प्रति तिरस्कार इसकी दुर्भावना का एक आधार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इज़राइल की कार्रवाइयों की निंदा करने वाले कई प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें प्रस्ताव 194 शामिल है, जो लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण 70 लाख से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थियों को उनके वापसी के अधिकार से वंचित किया गया है। हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 77/247 (2022) ने ICJ से इज़राइल के कब्जे पर सलाहकारी राय मांगी, जिसके परिणामस्वरूप ICJ का 19 जुलाई 2024 का निर्णय हुआ, जिसमें इज़राइल के वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम, और गाजा पर कब्जे को अवैध घोषित किया गया। ICJ ने इज़राइल को आदेश दिया: - अपने कब्जे को “जितनी जल्दी हो सके” समाप्त करने के लिए। - सभी नई बस्ती गतिविधियों को रोकने के लिए। - बस्तियों को खाली करने के लिए। - मुआवजा प्रदान करने के लिए (ICJ सलाहकारी राय, 2024)।

फिर भी, इज़राइल ने इन आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। बस्ती विस्तार बिना रुके जारी है, 2023 तक वेस्ट बैंक में 465,000 और पूर्वी यरुशलम में 230,000 बस्तीवासी हैं, और कोई निकासी नहीं हुई है। ICJ की जनवरी 2024 की अंतरिम उपाय, जो दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले के जवाब में जारी किए गए थे, ने इज़राइल को नरसंहारपूर्ण कृत्यों को रोकने और गाजा में मानवीय सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। हालांकि, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 26 फरवरी 2024 को बताया कि इज़राइल “न्यूनतम कदम उठाने में भी विफल रहा है,” सहायता को बाधित करके और भुखमरी को और बढ़ाकर (एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2024)। संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई 2025 को चेतावनी दी कि इज़राइल की नाकेबंदी के कारण 14,000 शिशु भुखमरी से तत्काल मृत्यु के खतरे में हैं (द गार्जियन, 2025)।

इज़राइल का इन निर्णयों को “गैर-बाध्यकारी” या राजनीति से प्रेरित मानकर खारिज करना अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति जानबूझकर की गई अवहेलना को दर्शाता है। यह अवहेलना संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों, जैसे कि युद्धविराम की मांग करने वालों, के प्रति इसके तिरस्कार को दर्शाती है, जिन्हें इज़राइल ने नजरअंदाज किया, और सैन्य अभियानों को जारी रखा, जिसने अक्टूबर 2024 तक 42,000 से अधिक फिलिस्तीनियों, जिसमें 13,300 बच्चे शामिल हैं, को मार डाला (एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2024)।

विभाजन योजना और दो-राष्ट्र समाधान को तोड़फोड़

इज़राइल की कार्यवाहियों ने व्यवस्थित रूप से प्रस्ताव 181 द्वारा परिकल्पित विभाजन योजना और दो-राष्ट्र समाधान को कमजोर किया है। 1947 की योजना ने मांडेट फिलिस्तीन का 56% हिस्सा यहूदी राष्ट्र और 43% हिस्सा अरब राष्ट्र को आवंटित किया था, जिसमें यरुशलम अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन था। हालांकि, 1948 में इज़राइल की स्थापना के साथ नकबा आई, जिसमें 750,000 फिलिस्तीनियों की जातीय सफाई हुई, और 78% फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया गया, जो आवंटित क्षेत्र से कहीं अधिक था। यह विस्तारवादी नीति 1967 में वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम, और गाजा के कब्जे के साथ जारी रही, जिन्हें इज़राइल ने कभी नहीं छोड़ा।

ओस्लो समझौते (1993-1995), जो दो-राष्ट्र समाधान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए थे, इज़राइल के अथक बस्ती निर्माण से कमजोर हो गए, जिसने फिलिस्तीनी क्षेत्र को खंडित कर दिया और एक व्यवहार्य फिलिस्तीनी राष्ट्र को असंभव बना दिया। 2024 तक, ICJ ने नोट किया कि इज़राइल का बस्ती शासन एक वास्तविक अनुबंध का गठन करता है, जो बल द्वारा क्षेत्र प्राप्त करने के निषेध का उल्लंघन करता है (ICJ सलाहकारी राय, 2024)। इज़राइल की शांति प्रक्रियाओं को तोड़फोड़, 2007 से गाजा की नाकेबंदी के साथ, एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना को रोकने की स्पष्ट मंशा को दर्शाती है, जो संयुक्त राष्ट्र की सह-अस्तित्व की दृष्टि के विपरीत है।

अंतरराष्ट्रीय कानून और यहूदी आदेशों का उल्लंघन

गाजा और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इज़राइल की कार्यवाहियां अंतरराष्ट्रीय कानून और यहूदी नैतिक आदेशों का घोर उल्लंघन करती हैं, जिससे यहूदी राष्ट्र होने का इसका दावा धोखा देता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

इज़राइल का आचरण 1948 की नरसंहार संधि और रोम संनियम के अनुच्छेद 6 के तहत नरसंहार की परिभाषा के साथ संरेखित है, जो नरसंहार को उन कृत्यों के रूप में परिभाषित करता है जो किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय, या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए जाते हैं। विशिष्ट उल्लंघनों में शामिल हैं: - **समूह के सदस्यों की हत्या:** अक्टूबर 2023 से 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी, जिसमें 14,500 बच्चे शामिल हैं, मारे गए हैं, जिनमें अंधाधुंध हमलों को ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा प्रलेखित किया गया है (ह्यूमन राइट्स वॉच, 2024)। - **गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाना:** नाकेबंदी ने कुपोषण का कारण बना है, जिसमें 60,000 गर्भवती महिलाओं को गर्भपात का बढ़ता जोखिम है (ह्यूमन राइट्स वॉच, 2024)। - **समूह को नष्ट करने की स्थिति थोपना:** संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्णित नाकेबंदी “विनाशकारी भुखमरी” का कारण बन रही है, जो 14,000 शिशुओं को भुखमरी से खतरे में डाल रही है (द गार्जियन, 2025)। - **नरसंहार के लिए उकसाना:** रक्षा मंत्री योआव गैलेंट जैसे बयान, “हम मानव पशुओं से लड़ रहे हैं,” और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का “अमालेक” का उल्लेख नरसंहारपूर्ण इरादे का संकेत देते हैं (एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2024)।

ये कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) का भी उल्लंघन करती हैं, जिसमें चौथी जिनेवा संधि के तहत सामूहिक दंड का निषेध शामिल है, और युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का गठन करती हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति ने उल्लेख किया है (OHCHR, 2024)।

यहूदी आदेशों का उल्लंघन

इज़राइल की कार्रवाइयां यहूदी धर्म के नैतिक मूल, जो तौरात, तलमुद, और हलाखा में निहित हैं, के विपरीत हैं: - **जीवन की पवित्रता (पिकुाच नेफेश)**: तौरात का आदेश "जीवन चुनें" (निर्गमन 30:19) मानव जीवन के संरक्षण को प्राथमिकता देता है। इज़राइल की नाकेबंदी, जो भुखमरी का कारण बनती है, इस सिद्धांत का उल्लंघन करती है। - **विनाश का निषेध (बाल ताश्चित)**: निर्गमन 20:19-20 युद्ध के दौरान फलदार वृक्षों को नष्ट करने पर रोक लगाता है, जिसे अनावश्यक विनाश के व्यापक निषेध के रूप में व्याख्या किया जाता है। गाजा की बुनियादी ढांचे का इज़राइल द्वारा विनाश इसका उल्लंघन करता है। - **शत्रुओं के प्रति दया**: नाखमानिदेस ने सिखाया, "हमें अपने शत्रु के साथ दयालुता से व्यवहार करना सीखना चाहिए" (माय ज्यूइश लर्निंग)। अमानवीय बयानबाजी और सामूहिक दंड इस नैतिकता के विपरीत है। - **गैर-लड़ाकों की सुरक्षा**: तलमुद आदेश देता है कि घेराबंदी के दौरान एक पक्ष को खुला रखा जाए ताकि नागरिक भाग सकें (गिट्टिन 45बी)। गाजा पर इज़राइल की घेराबंदी, जो नागरिकों को फंसाती है, इसका उल्लंघन करती है।

यहूदी विद्वान जैसे रब्बी शेरोन ब्राउस और संगठन जैसे ज्यूइश वॉयस फॉर पीस ने इज़राइल की कार्रवाइयों को यहूदी मूल्यों के विपरीत ठहराया है, यह तर्क देते हुए कि वे न्याय की भविष्यवाणीपूर्ण दृष्टि को धोखा देते हैं (IKAR, 2023)।

फिलिस्तीनियों का प्रतिरोध का अधिकार और इज़राइल का आत्मरक्षा का अभाव

अंतरराष्ट्रीय कानून स्पष्ट रूप से कब्जे वाले लोगों को प्रतिरोध का अधिकार देता है, जिसमें सशस्त्र साधनों के माध्यम से भी, जो उनके आत्मनिर्णय के अधिकार का हिस्सा है। अफ्रीकी चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स और संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 45/130 पुष्टि करते हैं कि कब्जे वाले लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए "सभी उपलब्ध साधनों" का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते वे IHL का पालन करें, जो नागरिकों पर हमला करने को रोकता है (प्रतिरोध का अधिकार, विकिपीडिया)। 1967 से इज़राइल के कब्जे के तहत रहने वाले फिलिस्तीनियों को यह अधिकार है, लेकिन इज़राइल उनके प्रतिरोध को आतंकवाद के रूप में लेबल करता है, उनकी कानूनी सुरक्षा को नकारता है।

इसके विपरीत, इज़राइल जैसे कब्जे वाली शक्ति को उस जनता के खिलाफ आत्मरक्षा का दावा करने का अधिकार नहीं है जिसे वह कब्जा करती है। चौथी जिनेवा संधि कब्जे वालों को नागरिकों की रक्षा करने के लिए बाध्य करती है, न कि उन्हें सैन्य बल के अधीन करने के लिए। अनुच्छेद 59(1) मानवीय सहायता को सुगम बनाने का आदेश देता है, लेकिन इज़राइल की नाकेबंदी और सैन्य अभियान इसका उल्लंघन करते हैं, जो युद्ध अपराधों का गठन करता है (AdHaque110, X पोस्ट, 2025)। जैसा कि कानूनी विद्वान फैसल कुट्टी ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, इज़राइल को कब्जे वाली जनता से अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं है" (faisalkutty, X पोस्ट, 2024)।

नरसंहार और दशकों की दंडमुक्ति

गाजा में इज़राइल की कार्रवाइयां नरसंहार संधि की नरसंहार की परिभाषा के साथ संरेखित हैं, जो दशकों की दंडमुक्ति का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति ने नवंबर 2024 में नोट किया कि इज़राइल की युद्ध विधियां, जिसमें भुखमरी शामिल है, "नरसंहार के साथ सुसंगत" हैं (OHCHR, 2024)। यह दंडमुक्ति निरंतर अंतरराष्ट्रीय निष्क्रियता से उत्पन्न होती है, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में अमेरिका के वीटो से, जिसने इज़राइल को जवाबदेही से बचाया है। ICJ निर्णयों और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों को लागू करने में विफलता ने इज़राइल के उल्लंघनों को प्रोत्साहित किया है, जिसका चरमोत्कर्ष रज़ सेगल द्वारा "नरसंहार का एक पाठ्यपुस्तक मामला" कहा गया है (Jewish Currents, 2023)।

फिलिस्तीनियों का आत्मनिर्णय का अधिकार बनाम इज़राइल का अस्तित्व का अभाव

फिलिस्तीनी लोगों को आत्मनिर्णय का अविचल अधिकार है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में निहित है और असंख्य संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों द्वारा पुष्टि की गई है। यह अधिकार एक संप्रभु राष्ट्र की स्थापना को शामिल करता है, जो कब्जे और दमन से मुक्त हो। इसके विपरीत, इज़राइल जैसे राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत “अस्तित्व का अधिकार” नहीं है; यह एक विशेषाधिकार है जो व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, जिनका जीवन का अधिकार मानव अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है। जैसा कि विद्वान जॉन क्विगली तर्क देते हैं, “अंतरराष्ट्रीय कानून में किसी भी राष्ट्र को अस्तित्व का अधिकार नहीं है; राष्ट्र मान्यता और कार्य के माध्यम से मौजूद हैं, न कि किसी अंतर्निहित अधिकार के माध्यम से” (Quigley, 2006)। फिलिस्तीनियों के विस्थापन पर निर्मित एक कब्जे वाली शक्ति के रूप में इज़राइल का अस्तित्व का दावा, फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के सामने नैतिक या कानूनी आधार की कमी रखता है।

इज़राइल की यहूदी राष्ट्र के रूप में गलत प्रस्तुति

इज़राइल का यहूदी राष्ट्र होने का दावा एक गंभीर गलत प्रस्तुति है जो यहूदियों को नकारात्मक प्रकाश में डालती है और उन्हें वैश्विक स्तर पर खतरे में डालती है। यहूदी धर्म को अत्याचारों, युद्ध अपराधों, और नरसंहार के साथ जोड़कर, इज़राइल धर्म के नैतिक आधारों को विकृत करता है। तौरात का आदेश, “तू परदेशी को सताएगा नहीं, क्योंकि तुम मिस्र देश में परदेशी थे” (निर्गमन 22:21), इज़राइल की विस्थापन और दमन की नीतियों के विपरीत है। IfNotNow और Jews for Racial & Economic Justice जैसे यहूदी संगठन इस समीकरण को खारिज करते हैं, यह दावा करते हुए कि इज़राइल की आलोचना यहूदी-विरोधी नहीं है, बल्कि यहूदी मूल्यों का बचाव है (In These Times, 2024)।

इज़राइल की आलोचना को यहूदी-विरोधी के साथ समान मानना एक आधुनिक रक्तपात का आरोप है, जो यहूदियों को गलत तरीके से राज्य के अपराधों से जोड़ता है और असहमति को दबाता है। यह यहूदी समुदायों को नाराजगी को बढ़ावा देकर और उन्हें उन नीतियों से जोड़कर खतरे में डालता है जिनका वे विरोध कर सकते हैं। जैसा कि अल जज़ीरा नोट करता है, “इज़राइल के युद्ध और कब्जे की आलोचना यहूदी-विरोधी नहीं है,” लेकिन यह भ्रम यहूदी-विरोधी हमलों को बढ़ाने का जोखिम उठाता है (अल जज़ीरा, 2024)।

निष्कर्ष

इज़राइल का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का पालन करने की गारंटी के माध्यम से प्राप्त किया गया था, लेकिन इसकी कार्यवाहियाँ—विस्तारवादी बस्तियाँ, नरसंहारपूर्ण नीतियाँ, और ICJ निर्णयों की अवहेलना—दुर्भावना दर्शाती हैं। सामान्य कानून के साथ समानता में, यह उल्लंघन इसकी सदस्यता को अमान्य कर सकता है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय कानून के तंत्र राजनीतिक बाधाओं का सामना करते हैं। इज़राइल की दो-राष्ट्र समाधान को तोड़फोड़, यहूदी आदेशों का उल्लंघन, और नरसंहार की परिभाषाओं के साथ संरेखण इसकी अवैधता को रेखांकित करता है। फिलिस्तीनियों को प्रतिरोध और आत्मनिर्णय का निर्विवाद अधिकार है, जबकि इज़राइल, एक कब्जे वाली शक्ति के रूप में, फिलिस्तीनी अधिकारों की कीमत पर आत्मरक्षा या अस्तित्व का दावा करने का अधिकार नहीं रखता। यहूदी राष्ट्र के रूप में इसकी गलत प्रस्तुति विश्व भर के यहूदियों को खतरे में डालती है, जो एक धर्म पर छाया डालती है जो न्याय और करुणा में निहित है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इज़राइल को जवाबदेह ठहराने, फिलिस्तीनी अधिकारों को बनाए रखने, और अंतरराष्ट्रीय कानून की अखंडता को बहाल करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए।

प्रमुख उद्धरण

- संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 273(III)
- संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 181(II)
- संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 194(III)
- ICJ सलाहकारी राय, 2024
- एमनेस्टी इंटरनेशनल ICJ निर्णय के अनुपालन पर
- द गार्जियन खतरे में शिशुओं पर
- ह्यूमन राइट्स वॉच गाजा पर
- OHCHR नरसंहार निष्कर्षों पर
- Jewish Currents नरसंहार पर

- अल जज़ीरा आलोचना पर
- प्रतिरोध का अधिकार, विकिपीडिया
- faisalkutty, X पोस्ट, 2024